



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

1. 11. 11. 11
11. 11. 11
11. 11. 11

सं० 234]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1978/वैशाख 16, 1900 (शक)

No. 234] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1978/VAISAKHA 16, 1900 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 1978

का० आ० 307 (अ) — राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 20 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1977 की निर्वाचन पिटीशन सं० 2 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 मार्च, 1978 को किए गए आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करती है।

“भारत के उच्चतम न्यायालय की आरम्भिक अधिकारिता वाली 1977 की निर्वाचन पिटीशन सं० 2 में

मदन लाल धर्तीयाकर'

पिटीशनर

बनाम

श्री नीलम मजीब रेड्डी और अन्य सभी

प्रत्यर्थी

निर्यात

व्या० सरकारिया

यह राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम के अधीन 19 अगस्त, 1977 को दाखिल की गई एक पिटीशन है जिसमें 19 जुलाई 1977 को हुए राष्ट्रपतीय निर्वाचन में भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री नीलम मजीब रेड्डी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।

पिटीशनर ने नाम-निर्देशन पत्र 5 जुलाई, 1977 को दाखिल किया किन्तु रिटनिंग आफिसर ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार

नाम-निर्देशन-पत्र पर प्रस्थापक या समर्थक के रूप में किसी निर्वाचक के हस्ताक्षर नहीं थे।

अतः यह सही है कि उसने अधिनियम की धारा 5 ख (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया। किन्तु पिटीशनर के पास ऐसे ब्यौरेवार कारण हैं कि उसे ऐसा कोई निर्वाचक क्यों न मिल सका जो उसके नाम-निर्देशन पत्र पर प्रस्थापक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करता।

जब मामला आज हमारे समक्ष आया तो पिटीशनर ने अनुरोध किया कि पिटीशन की सुनवाई अगले ग्रीष्मावकाश तक के लिए स्थगित कर दी जाए। हमने उसे यह स्पष्ट किया कि हम उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देता और सुनवाई स्थगित नहीं की गई।

इसके अन्त में पिटीशनर ने जोर देते हुए यह दलील दी कि पिटीशन विनिश्चय के लिए एक बड़ी बैठक की निर्देशन की जाए। हमने उसकी उन सभी दलीलों को जो वह इस सबंध में देना चाहते थे पूरी तरह से सुना और उन पर विचार किया, तथा हमें उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए उनमें कोई बजह दिखाई नहीं दी।

चूँकि अधिनियम (1952 का 31) की धारा 5 ख (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं हुआ अतः पिटीशनर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 13(1) के अर्थान्वयन में सम्यक-रूप से नाम-निर्देशन 'प्रत्यर्थी' नहीं था और इस प्रकार यह पिटीशन खाने के लिए उसे सुने जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है (1977 की निर्वाचन पिटीशन सं० 1 देखिए)।

तबनुसार हम खर्च का कोई आदेश किए बिना यह पिटोशन खारिज करते हैं।

ह०/-

(आर० एस० सरकारिया) न्या०

ह०/-

(एल० एल० ऊंटवालिया) न्या०

ह०/-

(जसवंत सिंह) न्या०

ह०/-

(पी० एस० कैलासम) न्या०

ह०/-

(वी० डी० तुलजापुरकर) न्या०

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1978.

[सं० एफ 23(4)/78—वि० II]

ई० वेकटेश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the May 6, 1978

S.O. 307(E).—In pursuance of section 20 of the Presidential and Vice-Presidential Election Act, 1952 (31 of 1952), the Central Government hereby publishes the Order made on the 9th March, 1978, by the Supreme Court of India, in Election Petition No. 2 of 1977.

“IN THE SUPREME COURT OF INDIA ORIGINAL JURISDICTION

ELECTION PETITION NO. 2 OF 1977

Madan Lal 'Dhartipakar'Petitioner.

Versus

Shri Neelam Sanjeeva Reddy & 11 Ors Respondents.

JUDGMENT

SARKARIA, J.

This is a petition filed by Shri Madan Lal 'Dhartipakar' on August 19, 1977 under the Presidential and Vice-Presidential Election Act, challenging the election of Shri Neelam Sanjeeva Reddy as President of India at the Presidential Election held on July 19, 1977.

The petitioner filed a nomination paper on July 5, 1977 but that nomination paper was rejected by the Returning Officer because—as he admits—it was not subscribed by any elector as proposer or as seconder.

He had thus admittedly not complied with the requirements of Section 5B(1) of the Act. The petitioner has, however, detailed reasons why he could not find any elector to propose or second his nomination papers.

When the case came up before us today, the petitioner requested that the hearing of the petition be postponed till after the coming summer vacation. We explained to him that we did not see any sufficient reason to accede to his request. The adjournment was declined.

The petitioner then argued at length urging that the petition should be referred to a larger Bench for decision. We have fully heard and considered all that he had to say in this connection, and we are not persuaded to accede to his request.

Since there was no compliance with the requirements of Section 5B(1) of the Act (No. 31 of 1952), the petitioner was not a duly nominated 'candidate' within the meaning of Section 13(i) of the Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Act, 1977. And, as such, has no locus standi to maintain this petition (vide Election Petition No. 1 of 1974).

Accordingly we dismiss the petition, but without any order as to costs.

Sd/-

(R. S. SARKARIA) J.

Sd/-

(N. L. UNTWALIA) J.

Sd/-

(JASWANT SINGH) J.

Sd/-

(P. S. KAILASAM) J.

Sd/-

(V. D. TULZAPURKAR) J.

New Delhi.

March 9, 1978.

[No. F. 23(4)/78-Leg. II]

E. VENKATESWARAN, Jt. Secy."